BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

गांवों का सशक्तिकरण, बिहार का सशक्तिकरण: विकसित भारत की दिशा में रोडमैप

ग्रामीण विकास को गति देना: बिहार के विकास को आकार देने वाली केंद्रीय पहल

आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं, वे भी गांवों से मिले सबक और अनुभवों से ही आकार ले रहे हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मुख्य बातें

- 7 अगस्त, 2025 तक, बिहार में **73.88 लाख से अधिक किसान** वित्त वर्ष 2025-26 में पीएम-किसान योजना से लाभान्वित होंगे।
- 7 अगस्त, 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत **1.57 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों** के पास नल के पानी के कनेक्शन होंगे।
- बिहार ने नवंबर 2018 में सौभाग्य योजना के माध्यम से **100% घरेलू विद्युतीकरण** का लक्ष्य हासिल किया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत **49 लाख से अधिक ग्रामीण आवास** स्वीकृत किए गए।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत **1.16 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन** दिए गए।

परिचय

जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है, भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी (2021 के आंकड़े) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिससे ग्रामीण विकास सरकार के नीतिगत एजेंडे में एक स्वाभाविक प्राथमिकता बन गया है। पिछले 11 वर्षों में, निरंतर प्रयासों ने गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार, समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है कि ग्रामीण भारत राष्ट्र की विकास यात्रा का

केंद्र बना रहे। विजन स्पष्ट रहा है - ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका में बदलाव लाना।

बिहार, जहां अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, इस एजेंडे का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 2014 के बाद से, राज्य में विकास की गति ने खासी बढ़ी है, जिससे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जमीनी स्तर पर ठोस लाभ हासिल करना सुनिश्चित हुआ है।

राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से ग्रामीण बिहार को मज़बूत बनाना

केंद्र सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज, केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार के सुदूर इलाकों तक भी बिना किसी देरी के पहुंच रही हैं।

पहले, ग्रामीण लोग अपनी आय का 50% से ज्यादा हिस्सा भोजन और जरूरी चीजों पर खर्च करते थे। आजादी के बाद पहली बार, ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पर होने वाला खर्च 50% से नीचे आया है, जो बढ़ती गैर जरूरी आय और बेहतर क्रय शक्ति को दर्शाता है।

क. आजीविका

- **बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ - 02 सितंबर, 2025** को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया और संस्था के खाते में ₹105 करोड़ हस्तांतरित किए।

  सहकारी संघ का उद्देश्य जीविका से जुड़े समुदाय के सदस्यों को समय पर और किफायती ऋण उपलब्ध कराना है। सभी पंजीकृत क्लस्टर-स्तरीय संघ इस सहकारी समिति का हिस्सा होंगे, जिसे केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन दिया जाएगा। पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली, जीविका दीदियों को सीधे और पारदर्शी धन हस्तांतरण सुनिश्चित करेगी, जिसकी सुविधा टैबलेट से लैस **12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं** द्वारा दी जाएगी।

  इस पहल से ग्रामीण महिला उद्यमिता को मजबूत करने और समुदाय-आधारित उद्यमों का विस्तार होने की उम्मीद है। शुभारंभ समारोह में लगभग 20 लाख महिलाओं की भागीदारी ने कार्यक्रम के व्यापक प्रभाव को दर्शाया।

प्रधानमंत्री ने 02/09/2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया

- **आजीविका - दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)**

  - केंद्र सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक बिहार को ₹6,181.41 करोड़ की पर्याप्त राशि आवंटित की है। इस महत्वपूर्ण निवेश का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी कम करना है।

  - 18 जुलाई, 2025 को, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोतिहारी में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों को ₹400 करोड़ जारी किए, जिससे राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को एक मजबूत गति मिली।

- बिहार ने **30.21 लाख** महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। **जुलाई 2025 तक,** राज्य में 20 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं, जो चल रही महिला सशक्तिकरण पहलों की सफलता को दर्शाता है।

ख. बुनियादी ढांचा विकास

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) -** सितंबर 2024 तक बिहार में ₹28,292 करोड़ की लागत से 53,419 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें और 1,153 पुल बनाए जा चुके हैं, साथ ही ₹5,229 करोड़ की लागत से 6,285 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कें और 194 पुलों का उन्नयन कार्य चल रहा है (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
- **22 अगस्त, 2025 को**, प्रधानमंत्री ने बिहार के गया में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक चार लेन वाले खंड का उद्घाटन किया, जिस पर लगभग ₹1,900 करोड़ की लागत आई है, जिससे भीड़भाड़ कम होगी, यात्रा का समय कम होगा और यात्री एवं माल ढुलाई में वृद्धि होगी। इसके अलावा, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-120 के बिक्रमगंज-दावथ-नवानगर-डुमरांव खंड के पक्के शोल्डर सहित दो लेन में सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क में सुधार होगा, जिससे स्थानीय आबादी के लिए नए आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे।
- **सौभाग्य योजना -** बिहार में नवंबर 2018 में सौभाग्य के तहत घरेलू विद्युतीकरण का स्तर 100% तक पहुंच गया है।
- **भारतनेट परियोजना -** बिहार में, भारतनेट चरण- I और चरण- II के तहत नियोजित **8,340 ग्राम पंचायतों** को अगस्त 2025 तक सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

ग. आवास एवं स्वच्छता

- **प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)**

  - पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ग्रामीण बिहार में **50.12 लाख से अधिक पक्के मकान** बनाने का संचयी लक्ष्य है, जिसमें से 49 लाख से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और 4 अगस्त, 2025 तक 38.39 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं।
  - 18 जुलाई, 2025 को बिहार के मोतिहारी में, प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश समारोह के तहत 12,000 लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपीं और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत **40,000 लाभार्थियों को ₹160 करोड़** से अधिक की राशि वितरित की।
  - 22 अगस्त, 2025 को बिहार के गया में, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश समारोह के तहत प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबियां सौंपीं।

- **स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) -** बिहार में, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत 2014 से जुलाई 2025 तक 1.39 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 9364 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है।

घ. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) -** वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 07 अगस्त, 2025 तक बिहार के **73.88 लाख** से अधिक पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)** -

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत **₹548.13 करोड़** के निवेश से **38 अनूठी पहलों** के माध्यम से बिहार का मत्स्य पालन क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।
- **18 जुलाई, 2025 को,** बिहार के मोतिहारी में, प्रधानमंत्री ने पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्य पालन और जलीय कृषि परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें नई मछली हैचरी, बायोफ्लोक इकाइयां, सजावटी मछली पालन, एकीकृत जलीय कृषि इकाइयां और मछली चारा मिलें शामिल हैं - ताकि बिहार में रोजगार, मछली उत्पादन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

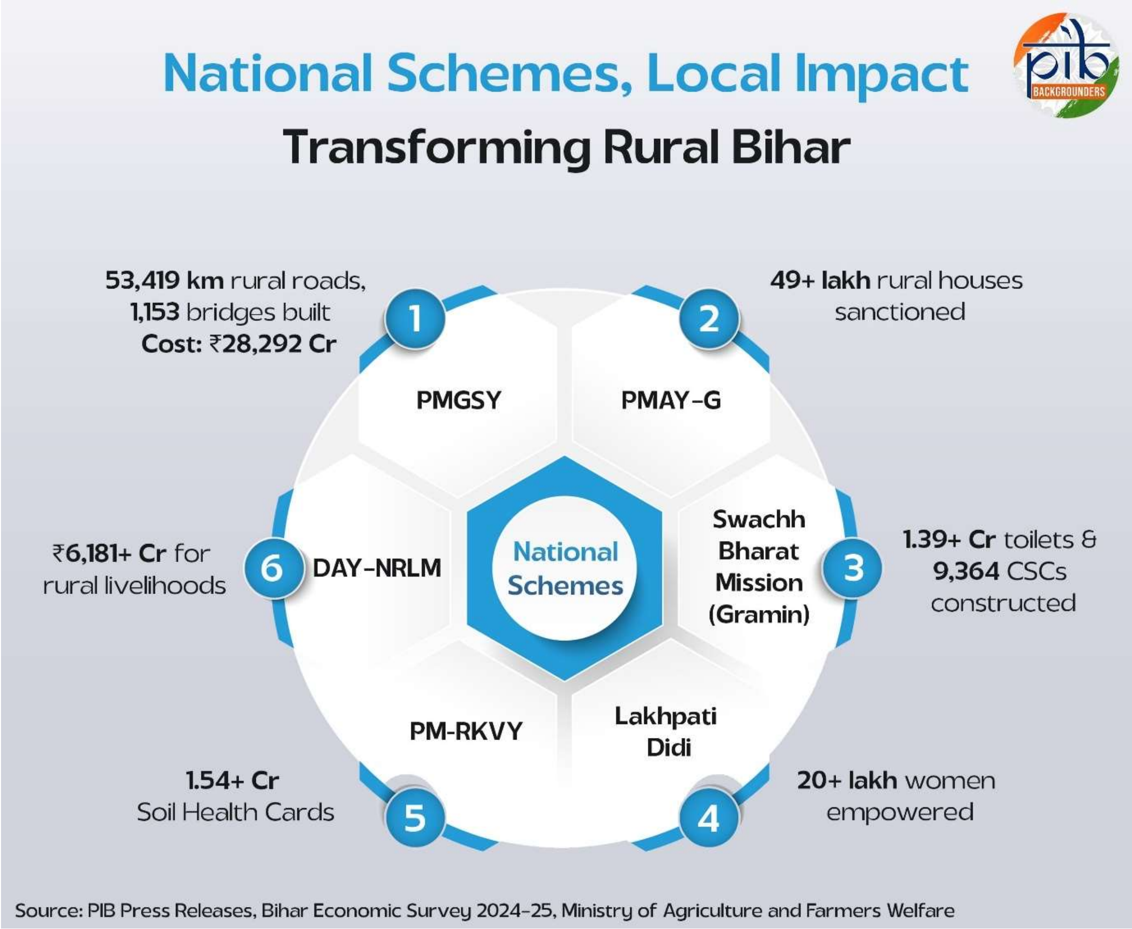

- **पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) -** जुलाई 2025 तक, इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, पीएम-आरकेवीवाई के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता घटक के अंतर्गत बिहार के किसानों को 1.54 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

- **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) -** पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, 30 जून, 2025 तक, बिहार के लिए ₹748.76 करोड़ के परिव्यय वाली कुल 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना से राज्य के 28,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
- बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इन गतिविधियों में लगे किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना उत्पादकों को सहायता और प्रशिक्षण

सहायता भी प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

- इस उपलब्धि को चिह्नित करते हुए, बिहार में फरवरी, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 10,000वें एफपीओ की स्थापना की गई। 10,000वां एफपीओ खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया है और यह मक्का, केला और धान पर केंद्रित है।

- पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा।

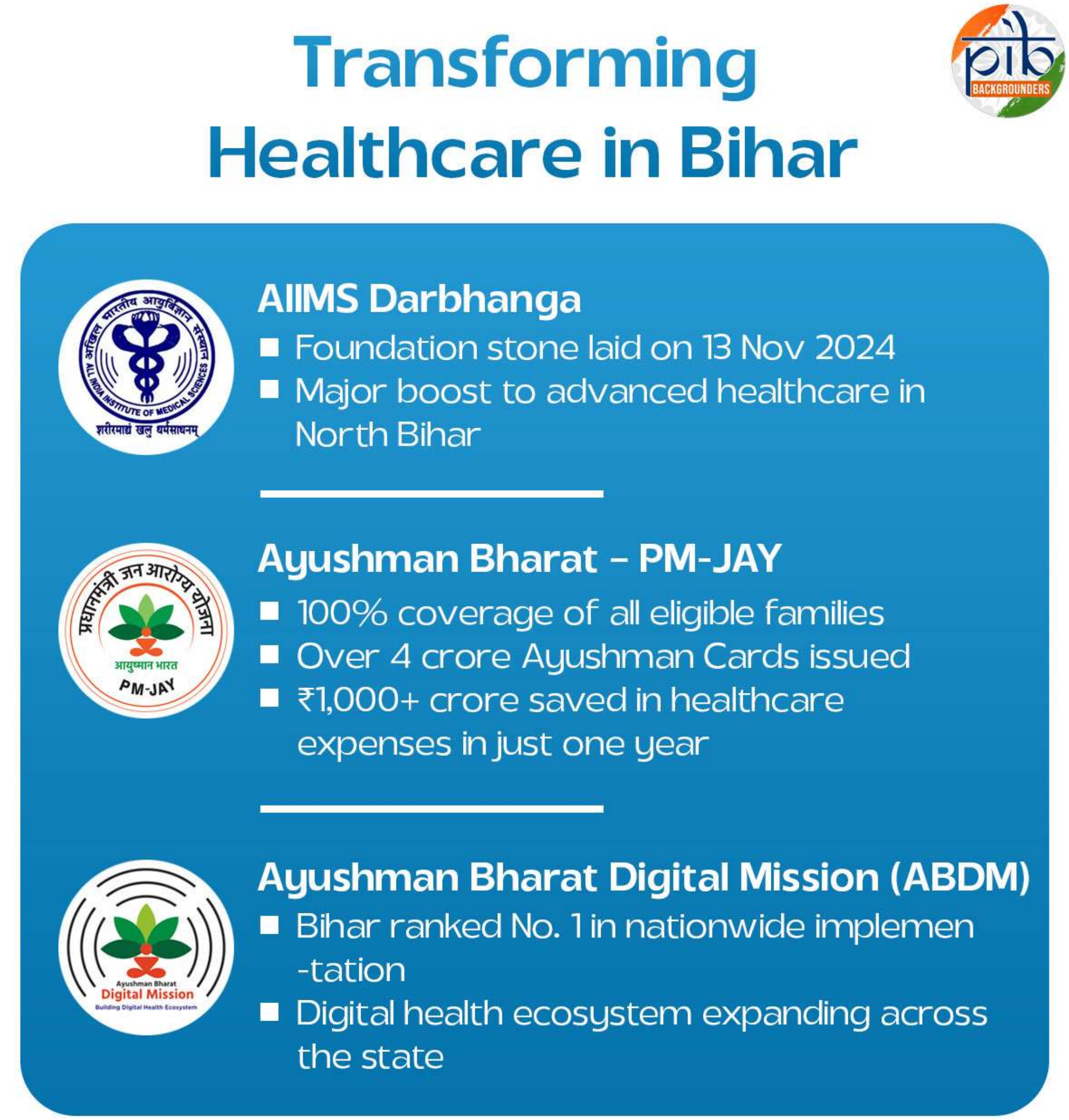

Source: PIB Press Releases, Ayushman Bharat Dashboard

ङ. पेयजल और स्वच्छ ऊर्जा

- **जल जीवन मिशन (जेजेएम) -** 07 अगस्त, 2025 तक, बिहार में 1.57 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) -** 01 अप्रैल, 2025 तक, पीएमयूवाई के तहत बिहार में ग्रामीण महिलाओं को 1.16 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

च. स्वास्थ्य

- **आयुष्मान भारत -** प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) - पीएम-जेएवाई के तहत, बिहार ने सभी पात्र परिवारों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। सितंबर 2025 तक, राज्य में 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इससे केवल एक वर्ष में ही बिहार के लोगों के स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च में ₹1,000 करोड़ से ज्यादा की बचत हुई है।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) -** एबीडीएम के कार्यान्वयन में भी बिहार ने नंबर 1 रैंक हासिल की है।
- 13 नवंबर, 2024 को, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स दरभंगा की आधारशिला रखी।

केंद्र सरकार के निरंतर ध्यान दिए जाने से बिहार का ग्रामीण विकास परिदृश्य बदल गया है। बुनियादी ढांचे, आवास एवं स्वच्छता, कृषि और मत्स्य पालन से लेकर आजीविका, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ ऊर्जा तक, इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है।

प्रमुख योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ रहे हैं और बुनियादी सुविधाएं हर घर तक पहुंच रही हैं। विकसित बिहार और उसके माध्यम से विकसित भारत का सपना अब वास्तविकता के करीब पहुंच रहा है।

संदर्भ:

- **PIB**
  1. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1894901
  2. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090098
  3. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2145773
  4. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2145752
  5. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2137954
  6. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2137959
  7. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159719

8. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163021
9. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155676
10. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098516
11. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2105822
12. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153494
13. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2072982
14. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2134745
15. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2134986
16. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155028
17. https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186011

- PM's Quote: https://x.com/narendramodi/status/864484422585696257
- Other
    1. https://pmkisan.gov.in/
    2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1087731940206706&id=100069097304324&set=a.296831112630130
    3. https://ppac.gov.in/consumption/state-wise-pmuy-data
    4. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1520_Snu5qh.pdf?source=pqals
    5. https://dashboard.nha.gov.in/public/
    6. https://state.bihar.gov.in/finance/cache/12/07-Mar-25/SHOW_DOCS/Economic%20Survey%20Final%2022.02.2025%20%20English_11zon.pdf
    7. https://lakhpatididi.gov.in/state-wise-targets/

पीके/केसी/एमपी